न्यायमूर्ति जं. वी. गुप्ता के समक्ष

उर्मिला देवी, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरि प्रकाश, — *उत्तरदाता*

सिविल पुनरीक्षण सं. 3163 सन् 1986

जनवरी 5, 1987

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV)— धारा 24 — पति और पत्नी दोनों द्वारा वादकालीन भरण-पोषण देने के लिए आवेदन — विचारण न्यायलय ने पाया कि किसी भी पक्ष के पास पर्याप्त साधन नहीं थे स्वयं के भरण-पोषण करने के लिए — अदालत ने निष्कर्ष दर्ज करते हुए कहा कि सक्षम व्यक्ति होने के कारण पति काम करने में सक्षम था — पति ने कहा— क्या उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना आवश्यक हैं और अधिनियम की धारा 24 के तहत वादकालीन भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अभिनिर्णित, यदि पति काम करने में सक्षम व्यक्ति है, तो, उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना होगा और धारा 24 के तहत आवश्यक भरण-पोषण का भुगतान करना होगा । आवेदक की अपनी आय और प्रतिवादी की आय क्या है को धारा 24 के तहत राशि तय करने के उद्देश्य से विचार में लिया जाता है। किसी भी पक्ष की आय के अभाव में, पति एक सक्षम व्यक्ति है और काम करने में सक्षम है, उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में सक्षम माना जा सकता है और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। (पैरा 6)

सीपीसी की धारा 115 के तहत याचिका जो, श्री के.सी. डांग, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल की अदालत के आदेश, दिनांक 16 सितंबर, 1986 जिसके द्वारा लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना आवेदनों को खारिज कर दिया गया से उत्पन्न है।

दावा: हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह- विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए याचिका।

पुनरीक्षण में दावा: निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

वी. के. बाली, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए ।

जे. सी. वर्मा, अधिवक्ता, उत्तरदाता के लिए ।

निर्णय

यह आदेश 1987 संख्या 54 की सिविल पुनरीक्षण याचिका का भी निपटान करेगा, क्योंकि ये दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) के तहत दोनों पक्षों द्वारा दायर आवेदनों पर पारित एक ही आदेश से उत्पन्न हुई हैं।

2. प्रतिवादी हरि प्रकाश बंसल ने क्रूरता के आधार पर अपनी याचिकाकर्ता पत्नी उर्मिला देवी के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की। उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, दोनों पक्षों ने इस आरोप पर कि उनके पास एक-दूसरे को बनाए रखने के लिए कोई स्वतंत्र और पर्याप्त साधन नहीं है, लंबित गुजारा भत्ता और मुकदमेबाजी के खर्च के अनुदान के लिए अधिनियम की धारा 24 के तहत आवेदन दायर किए। जबकि पति का आरोप है कि उसकी पत्नी 20 हजार रुपये से ज्यादा कमाती थी. सिलाई का काम करके प्रति माह 500 रुपये कमाने वाली पत्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उसके पति की आय 500 रुपये प्रति माह है। 1,000/- रुपये की ब्याज आय के अलावा किरयाना दुकान से प्रति माह 3,000/- रुपये मिलते हैं। यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह 8 दिसंबर, 1984 को हुआ था और तलाक के लिए याचिका फरवरी, 1986 में दायर की गई थी। पत्नी ने 24 अप्रैल, 1986 को अधिनियम की धारा 24 के तहत आवेदन दायर किया था, जबकि पति ने 4 जून, 1986 को जवाबी कार्रवाई के रूप में आवेदन दायर किया। विद्वक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न तो पति और न ही पत्नी के पास खुद को या दूसरे पति या पत्नी को समर्थन देने के लिए कोई स्वतंत्र और पर्याप्त आय साबित हुई। उक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, यह माना गया कि उनमें से कोई भी दूसरे से भरण-पोषण की लंबित राशि या मुकदमेबाजी की लागत के अनुदान का हकदार नहीं था। पत्नी ने 1986 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 3165 दायर की, जबकि पति ने लागू आदेश के खिलाफ 1987 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 54 दायर की।

3. याचिकाकर्ता पत्नी के विद्वक अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत द्वारा यह गलत ठहराया गया था कि पति की अपनी कोई पर्याप्त आय नहीं थी, जबकि पत्नी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित हो गया था कि वह किराना दुकान चला रहा था और वहां से 3,000/- प्रति माह रुपये कमा रहा था। हालाँकि, पूरे साक्ष्य की सराहना करने पर, विद्वक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा यह पाया गया कि किसी भी पक्ष के पास एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र और पर्याप्त आय नहीं थी, तथ्य की खोज में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में।

4. इस स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता पत्नी के विद्वक अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही यह मान लिया जाए कि पति की अपनी कोई आय नहीं है, फिर भी, एक सक्षम व्यक्ति होने और एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी काम करने में सक्षम होने के नाते मजदूर या अन्यथा, उसके लिए भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। विवाद के समर्थन में, विद्वक अधिवक्ता ने *गुरमेल सिंह बनाम भुचरी,* (1)*; रणजीत कौर बनाम जगदेव सिंह,* (2) 1986(1) और *परमजीत कौर बनाम जगदीश सिंह* पर निर्भरता ली गई। प्रतिवादी पति के विद्वक अधिवक्ता द्वारा *देव राज बनाम हरजीत कौर* (4), और *श्रीमती लीला देवी बनाम तरलोक चंद* (5) के विपरीत दृष्टिकोण वाले निर्णयों को उद्धृत किया गया था।

5. श्रीमती *लीला देवी के मामले* (सुप्रा) में विद्वक एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को *गुरमेल सिंह* के मामले (सुप्रा)) में इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा विचार किया गया था और यह विचार किया गया कि श्रीमती लीला देवी के मामले का फैसला उस मामले के तथ्यों पर किया गया था और विद्वक एकल न्यायाधीश द्वारा कानून का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था। विद्वक एकल न्यायाधीश ने प्रश्न को एक बड़ी पीठ के पास भेजा और निर्णय *गुरमेल सिंह* के मामले में (सुप्रा) खण्ड न्यायपीठ द्वारा लिया गया था:

> "क्या एक सक्षम व्यक्ति एक साधारण मजदूर के रूप में भी काम करने में सक्षम है या जो अपने पिता या किसी अन्य रिश्तेदार के खेत या किसी अन्य प्रकार के प्रतिष्ठान पर काम करता है, उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में सक्षम माना जा सकता है और इस प्रकार उसे अंतरिम भुगतान करना पड़ सकता है। जब वह उनके बीच किसी वैवाहिक विवाद में उल्लिखित कारणों से उससे अलग रह रही होती है तो उसे भरण-पोषण मिलता है।"

उक्त प्रस्ताव पर विचार करते समय, खण्ड न्यायपीठ द्वारा यह प्रेक्षित किया गया:

> "यह कानून के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पिता के साथ काम कर रहा है, तो उसकी कोई आय नहीं है। उस संदर्भ में, यह एक प्रासंगिक विचार हो सकता है कि एक व्यक्ति सक्षम है और काम करने में सक्षम है यहां तक कि एक साधारण मजदूर के रूप में या अन्यथा। इस मामले में याचिकाकर्ता पति की ओर से यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सिर्फ इसलिए कि वह अपने पिता के साथ काम कर रहा है; उसकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है और यह अपनी पत्नी को धारा 24 के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित करने के लिए पर्याप्त है।"

(1) 1980 Curr. L.J. 193.
(2) 1986(1) H.L.R. 83.
(3) 1985(1) H.L.R. 204.
(4) 1981 H.L.R. 416.
(5) 1978 P.L.R. 744.

इसी तरह का दृष्टिकोण *रंजीत कौर* के मामले (सुप्रा) में लिया गया था, जिसमें विद्वक एकल न्यायाधीश ने निर्धारित किया था, -

"जहां तक वादकालीन भरण-पोषण का संबंध है, मेरा विचार है कि पत्नी कम से कम 100 रुपये प्रति माह और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 300 रुपये की हकदार है। भले ही पति की आय पर विचार किया जाए। न्यूनतम मजदूरी के बराबर जो एक सक्षम व्यक्ति प्रति माह 100 रुपये कमा सकता है क्योंकि वादकालीन भरण-पोषण बहुत मामूली होगी।

गुरमेल सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के फैसले के बाद, *परमजीत कौर* के मामले (सुप्रा) में इसे फिर से इस प्रकार निर्धारित किया गया:

"प्रतिवादी (पति) एक सक्षम व्यक्ति है और अपने पिता के साथ दर्जी के रूप में काम करता है। वह एक कुशल व्यक्ति है और यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि वह प्रति माह लगभग 1,000 रुपये कमाता होगा।"

6. इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम है, तो, उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना होगा और धारा 24 के तहत आवश्यक भरण-पोषण का भुगतान करना होगा । आवेदक की अपनी आय और प्रतिवादी की आय क्या है को धारा 24 के तहत राशि तय करने के उद्देश्य से विचार में लिया जाता है। किसी भी पक्ष की आय के अभाव में, पति एक सक्षम व्यक्ति है और काम करने में सक्षम है, उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में सक्षम माना जा सकता है और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

7. मामले के इस दृष्टिकोण में, पति की आय को न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानते हुए, जो एक सक्षम व्यक्ति कमा सकता है, रुपये की राशि। 100/- प्रति माह वादकालीन भरण-पोषण और रु. 100/- मुकदमेबाजी खर्च के रूप में, जिसकी पत्नी अपने आवेदन की तारीख से अधिनियम की धारा 24 के तहत पति से हकदार होगी।

8. परिणामस्वरूप, 1986 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 3163 अनुज्ञात की जाती है जबकि 1987 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 54 को लागतों के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन*

और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा